



रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार को बढ़ाएगा बजट

नोएडा, 1 फरवरी (नवोदय टाइम्स): शहर में तेजी से गिरते रियल स्टेट बाजार को नई गति देने का प्रयास किया गया है। रियल स्टेट से जुड़े लोग इस बजट को रियल स्टेट क्षेत्र में संजीवनी मान रहे हैं। उनका कहना है कि एमएसएमई सेक्टर बढ़ेगा इससे रोजगार बढ़ेगा और प्रापर्टी का ठंडे बाजार में तेजी आएगी। हालांकि अब भी ऐसी परियोजनाएं जिनको बजट से उम्मीद थी और वह स्ट्रैस फंड के साथ विशेष पैकेज चाहती थी उनके लिए बजट उम्मीद पर खरा नहीं उतरा।

मनोज गौड़ (एमडी, गौड़ ग्रुप और चेयरमैन) वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाएं रियल एस्टेट के नजरिए से मिश्रित बैग हैं। हालांकि, कम दरों और कोई छूट के साथ आयकर व्यवस्था का सरलीकरण, एक और वर्ष तक किफायती आवास के लिए घोषित उपायों का विस्तार इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक हैं।



धीरज जैन, (डायरेक्टर, महागुन ग्रुप) हालांकि इस बजट से रियल एस्टेट को सीधे तौर पर कुछ नहीं मिला है लेकिन ऐसी घोषणाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस सेक्टर की मदद करेंगी। इसका सीधा फायदा अफोर्डेबल हाउसिंग टैक्स हॉलिडे से मिलेगा जिसे मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है और टैक्स को वापस ले लिया गया है।



सागर सक्सेना, प्रोजेक्ट हेड, स्पेक्ट्रम मेट्रो सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 100 लाख करोड़ की घोषणा टियर 2 व टियर 3 शहरों के प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी लाएगी। हालांकि ऐसे कई मुद्दे थे जिनका संज्ञान लेने के लिए हम सभी सरकार से उम्मीद कर रहे थे।

मनप्रीत सिंह चड्ढा, (प्रमोटर वेव ग्रुप) - सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए 100 लाख करोड़ रुपये बनाने का फैसला किया है, जो टियर दो और टियर तीन जैसे शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। हम इस बजट में उल्लेखित इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर भी स्वागत करते हैं। बजट को ध्यान में रखते हुए, किफायती आवास ऋण पर मार्च 2021 तक चुकाए गए ब्याज पर

अतिरिक्त 1.5 लाख कर लाभ को भी बढ़ा दिया है।

धीरज बोरा, (हेड मार्कोम, पैरामाउंट ग्रुप) - सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 100 लाख करोड़ की घोषणा टियर 2 व टियर 3 शहरों के प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी लाएगी। हालांकि ऐसे कई मुद्दे थे जिनका संज्ञान लेने के लिए हम सभी सरकार से उम्मीद कर रहे थे।

मनोज गौड़ (एमडी, गौड़ ग्रुप और चेयरमैन) वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाएं रियल एस्टेट के नजरिए से मिश्रित बैग हैं। हालांकि, कम दरों और कोई छूट के साथ आयकर व्यवस्था का सरलीकरण, एक और वर्ष तक किफायती आवास के लिए घोषित उपायों का विस्तार इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक हैं।

